

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 7

MTT-054

अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डो.टो.)
(संशोधित)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

एम.टी.टी.-054 : प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक अनुवाद

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : भाग-I में से कुल तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है। भाग-II में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

भाग—I

नोट : प्रश्न संख्या 1-4 में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 700 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है।

P. T. O.

1. प्रशासनिक अनुवाद संबंधी सामान्य भूलों और उनके संभावित समाधानों की सोदाहरण चर्चा कीजिए। 20
2. प्रशासनिक भाषा से क्या अभिप्राय है ? प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग की सीमाओं और संभावनाओं पर विचार कीजिए। 20
3. विधि-अनुवाद की चुनौतियों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। 20
4. वाणिज्य-व्यापार में बैंकों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बैंकों में हिंदी प्रयोग और अनुवाद की आवश्यकता पर विचार कीजिए। 20
5. निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 350 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 10
 - (क) बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की पूर्वापेक्षाएँ
 - (ख) पर्यटन क्षेत्र में अनुवादकों के लिए अवसर

भाग—II

6. निम्नलिखित में से किन्हीं **दस** शब्दों के हिंदी पर्याय

लिखिए : 5

- (i) Performance Budget
- (ii) Unemployment
- (iii) Coalition Government
- (iv) Financial Provision
- (v) Nomination Paper
- (vi) Underground Railway
- (vii) Working Knowledge
- (viii) Sexual Harassment
- (ix) Pro-Vice Chancellor
- (x) Economic Advisor
- (xi) Chief Information Commissioner
- (xii) Superintendent of Police

7. निम्नलिखित में से किन्हीं **पाँच** अभिव्यक्तियों के हिन्दी

पर्याय लिखिए : 5

- (i) Explanation may be called for

- (ii) Before the effective date of government order
 - (iii) Copy forwarded for information please
 - (iv) Draft reply is put up for approval
 - (v) After taking into consideration all aspects of the issue
 - (vi) During the course of discussion
8. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच वाक्यों का हिंदी में

अनुवाद कीजिए :

5×2=10

- (i) The Photostat machine has now been installed and it has commenced functioning.
- (ii) The suggestion has been considered on several occasions earlier but was not accepted for reason stated above.
- (iii) The date of filling in the nomination form has not been recorded.

- (iv) Head of account has not been given on this bill.
- (v) In case you are not a manufacturer, you should quote the manufacturer's name.
- (vi) The Section Officer may submit the report.
9. निम्नलिखित अनुच्छेद का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

15

In accordance with the instruction of the Ministry of Home Affairs, it is essential that all the Class-IV employees should put on neat and clean uniform. It has been noticed that in spite of repeated instructions, several Class-IV employees do not put on their uniform or wear unclean uniform while on duty in the office. The Class-IV employees are once again instructed that during office hours they should invariably put on neat and clean uniform supplied to them. Hence, all Class-IV employees of the Department are advised to strictly comply with these instructions. In future, if any such employee is found without uniform, he/she will

be sent back home and will be treated on leave without pay for that day. Further, if any employee is wearing unclean uniform, not only his washing allowance will be stopped but disciplinary action will also be taken against him/her.

This order has been issued with the approval of the competent authority.

10. निम्नलिखित अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए : 15

किसी भी देश की विदेश नीति में एक मुद्दे के तौर पर मानव अधिकार एक या उससे अधिक कारणों से कुछ विशेष समस्याएँ खड़ी करता है। आम विचार यह है कि मानव अधिकार राज्य की संप्रभुता के क्षेत्र में आते हैं। किन्तु, व्यापक तौर पर इसे स्वीकार किया जाता है कि मानव अधिकार राज्य के अधिकार-क्षेत्र से बाहर का विषय भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह एक मान्य सिद्धांत है। अन्य शब्दों में, देशों की विदेश नीति में मानव अधिकार संबंधों में निपटने के संदर्भ में टकराव राज्य के अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उभरता

है। यह अपेक्षाकृत कठिन और समाधान होने वाला टकराव 'संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र' में परिलक्षित होता है। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करता है। इसलिए मानव अधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए किसी भी देश के रिकॉर्ड का आकलन उपर्युक्त सिद्धान्त के आलोक में करना होता है।